

- मधुमक्खीपालन को पहली बार मिली दस करोड रूपए की राशि
- श्री राधा मोहन ने किया मधुमक्खी से संबंधित पत्रिका का विमोचन

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि देश में मधुमक्खीपालन को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड को इस वर्ष दस करोड रूपए की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक योजना का अनुमोदन किया गया है। मधुमक्खी से संबंधित पत्रिका और गाइड के विमोचन के मौके पर श्री राधा मोहन सिंह ने जब दस करोड रूपए की राशि जारी करने की घोषणा की तो कार्यक्रम में उपस्थित बोर्ड के अधिकारियों ने विशेष रूप से अभार व्यक्त किया।

असल में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड का वर्ष 2006 में पुर्नगठन तो किया गया था लेकिन कभी भी इस बोर्ड को इतनी धनराशि नहीं मिल पाई। उदाहरण के लिए वर्ष 2010—11 में 2.56 करोड, वर्ष 2011—12 में 2.77, वर्ष 2012—13 में मात्र 19 लाख रूपए मिले और वर्ष 2013—14 में 2.21 करोड और 2014—15 में 35 लाख रूपए ही मिले। जब यह बात केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह को पता चली तो उन्होंने इस दिशा स्वयं पहल करते हुए मधुमक्खीपालन को हर स्तर पर बढ़ावा देने का फैसला किया। इस अवसर पर श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि मधुमक्खी पर्यावरण और कृषि विकास में मदद करती है और प्राकृतिक विविधता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि कई अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि मधुमक्खी सबसे अधिक क्षमता वाली पर परागणकर्ता है जिसे फसल की जरूरत, उचित समय व क्षेत्र के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। मधुमक्खियों द्वारा अच्छी क्षमता के पर परागण से कई फसलों जैसे फलों व सब्जियों, तिलहन, दलहन आदि की पैदावार में बढ़ोत्तरी होती है।

श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि मधुमक्खीपालन देश में कृषि के एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है। जो न केवल शहद, मोम, पराग, प्रोपोलिस, रायल जेली व बी वेनम जैसे बहुमूल्य पदार्थों का उत्पादन करता है बल्कि वनस्पति / फसलों की परागण क्रिया में सहयोग द्वारा पैदावार में बढ़ोत्तरी करने के साथ साथ ग्रामीण समुदाय के लिए रोजगार सृजन कर रहा है। देश में दो लाख मधुपालक हैं और बीस लाख मधुमक्खी की कालोनी हैं। देश में शहद का उत्पादन लगभग 80 हजार टन प्रतिवर्ष है। लगभग एक हजार करोड रूपए का निर्यात कारोबार है। मधुमक्खी के इस महत्व को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी नेशनल बी बोर्ड —

एन.बी.बी का पुर्नगठन के साथ साथ बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों मधुमक्खीपालकों के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण, गोष्ठी आदि कार्यक्रम शामिल हैं। मधुमक्खी से संबंधित पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य भी लोगों को और मधुमक्खी पालकों को जागरूक करना है।